* 20th Year
* Issue: 143
* 26.09.2026 (SATURDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

उत्तर प्रदेश का ब्रह्मोस उड़ा रहा पाकिस्तान की नींद, ग्रेटर नोएडा से शाह की हुंकार

ग्रेटर नोएडा २५/०९ (संवाददाता): गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को उज़्र प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कहा कि राज्य में बन रही ब्रह्मोस मिसाइलों की वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने राज्य की बढ़ती डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और निवेश के माहौल पर ज़ोर दिया। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एज़्सपो सेंटर एंड मार्ट में क्क इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे एडिशन के उद्घाटन के मौके पर शाह ने कहा कि उज़्र प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी छह नोड्स झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर में निवेश आ रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस फैसिलिटी का ज़िक्र करते हुए शाह ने कहा आज क्क में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान

की नींद उड़ा रही हैं; यह हो रहे बदलाव का एक बड़ा संकेत है। उन्होंने राज्य में डिफेंस प्रोडज़्शन के विस्तार के उदाहरण के तौर पर अमेठी में बनी्र्च-203 असॉल्ट राइफलों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा इसी तरह, अमेठी में बनी AK-203 असॉल्ट राइफलें नज़्सलियों और आतंकवादियों, दोनों की नींद उड़ा रही हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन मई 2025 में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर किया गया था। यह फैसिलिटी सुपरसोनिक ज़्रूज़् मिसाइल की असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम करती है। यहाँ बनी ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को अज़्टूबर 2025 में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह फैसिलिटी लगभग 200 एकड़ ज़मीन पर करीब ?300 करोड़ के निवेश से बनाई गई थी। इसका मकसद देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करना और सहायक उद्योगों व कुशल रोज़गार का इकोसिस्टम तैयार करना था।

शाह ने कहा कि ग्लोबल उथल-पुथल के बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया है। उन्होंने एज़्सपोर्ट के मौके बढ़ाने का श्रेय मोदी सरकार की आर्थिक और व्यापार नीतियों को दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की सोच पूर्वाग्रह से भरी है, वे भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (स्नञ्ज) किए हैं। शाह ने कहा इन समझौतों ने हमारे उद्योगों की निर्यात क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद हमने अपनी विकास दर बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आ रहे निवेश से न सिर्फ़ उज़्र प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में डिफेंस से जुड़े उत्पाद बनाने में मदद मिल रही है। शाह ने %एक ज़िला, एक उत्पाद% (ह्रष्ठह्रक्क) पहल का भी ज़िक्र किया और कहा कि इससे उज़्र प्रदेश के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले युवाओं को नौकरी की तलाश में राज्य छोड़कर जाना पड़ता था, जबकि अब स्थानीय उद्योगों के विकास से उन्हें घर के पास ही ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं।

चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का जवाब दें सीईसी ज्ञानेश कुमार-चिराग पासवान

नयी दिल्ली २५/०९ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, और खासकर मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनावी प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों का मजबूती से जवाब देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनावों में जनता का भरोसा कम न हो। उन्होंने कहा कि अगर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मेरा मानना ??है कि ष्टश्वष्ट की यह जिज़्मेदारी है कि वे मजबूती से अपना पक्ष रखें। अगर लोगों के मन में चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह है, तो यह गलत है। चुनाव आयोग को अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए ताकि लोगों के मन में कोई संदेह न रहे। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस मांग के जवाब

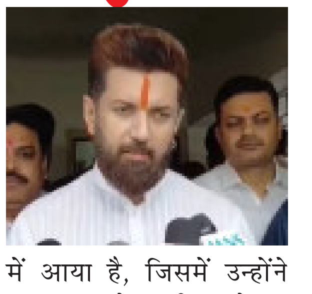

में आया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की %स्पेशल इंटेंसिव रिविजन% (स्ढ्ढक्र) प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। चिराग का कहना है कि चिंताओं को दूर करना चुनाव आयोग की ज़िज़्मेदारी है।

चिराग ने यह भी कहा कि उन्हें विपक्ष द्वारा ऐसे मुद्दे उठाने से कोई परेशानी नहीं है, ज़्योंकि राजनीति करना उनका काम है। हालांकि, उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठने वाली चिंताओं का समाधान करना चुनाव आयोग की ज़िज़्मेदारी है। यह घटनाक्रम द इंडियन एज़्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि हाल के महीनों में ष्टश्वष्ट ज्ञानेश कुमार से उनके दो सहयोगियों ने वोटर डेटाबेस की विश्वसनीयता, नए वोटरों को जोड़ने की प्रक्रिया में बदलाव और वोटर लिस्ट की सुरक्षा को लेकर बार-बार सवाल किए थे।

गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देशद्रोही कहा ज़्योंकि उन्होंने भारत के वोट को बर्बाद किया, और मांग की कि ष्टश्वष्ट को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव पूरी तरह से फ़र्ज़ी थे। उन्होंने कुमार को सरकारी गवाह बनने की सलाह दी और कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने यह मानकर अच्छा काम किया है कि वोट चोरी हो रही है।

छग में भारी बारिश, सीएम साय ने शनिवार को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया

रायपुर २५/०९ (संवाददाता): छज़्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुज़्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार, 26 सितंबर को राज्य के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए मुज़्यमंत्री ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शनिवार को सभी स्कूलों में अवकाश रखने के निर्देश दिए हैं। मुज़्यमंत्री ने कहा, ''भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव, नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि तथा आवागमन में कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में स्कूली बच्चों को किसी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर के विद्यालयों में अवकाश रखने का निर्णय लिया गया है।'' साय ने अभिभावकों से बच्चों

को घर पर रखने, सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का अनुरोध किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुज़्यमंत्री ने संबंधित विभागों और सभी जिला कलेज़्टरों को आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बस्तर संभाग सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित जिला कलेज़्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने को कहा है। मुज़्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। साय ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की लगातार निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि निचले इलाकों तथा नदी-नालों के आसपास बसे गांवों और बस्तियों पर विशेष नजर रखी जाए। जलस्तर बढ़ने या बाढ़ की आशंका होने पर लोगों को समय रहते सचेत किया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। अधिकारियों के अनुसार, मुज़्यमंत्री ने आगामी दिनों में लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत एवं बचाव दलों को आवश्यक संसाधनों के साथ तैयार रखने को कहा है। साय ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों के लिए आवश्यकता के अनुसार सुरक्षित आश्रय, भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुज़्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ और जलभराव की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने जिला कलेज़्टरों से मैदानी अमले को सक्रिय रखने तथा स्थानीय स्तर पर मिलने वाली प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने एनडीपीएस एक्स से टकराव पर लौटाया बंगाल का गुंडा रोधी बिल

नयी दिल्ली २५/०९ (संवाददाता): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल सरकार के गुंडा रोधी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हुए इसके एक ऐसे प्रावधान पर आपज़्ति जताई है, जो केंद्र के मादक पदार्थ रोधी कानून से टकरा सकता है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 (गुंडा रोधी विधेयक) जून में राज्य विधानसभा ने पारित किया था। इसके जरिये, संगठित अपराध, जबरन वसूली, अवैध खनन, साइबर अपराध और सार्वजनिक अव्यवस्था से निपटने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। अधिकारी ने बताया कि विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने स्वापक औषधि एवं मनऱ्प्रभावी पदार्थ

(एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 जैसा ही एक प्रावधान (इस विधेयक में) होने को लेकर पुनर्विचार के लिए इसे वापस भेज दिया। जिस प्रावधान की बात हो रही है, वह धारा 2(डी)(3)(बी) है। विधेयक वापस करने से पहले केंद्र सरकार की ओर से जारी 'नोट' में बताया गया कि इस प्रावधान के तहत एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने, उसकी कोशिश करने, उकसाने, बढ़ावा देने, विज़्पोषण करने या उसमें मदद करने वाले व्यक्ति को ''गुंडा'' माना जाएगा। इसमे यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रावधान के दायरे में वे मामले भी आ सकते हैं जो पहले से ही पीआईटी एनडीपीएस (स्वापक औषधि और मनऱ् प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण) अधिनियम, 1988 के तहत आते हैं। यह एक केंद्रीय कानून है जो खास तौर पर मादक पदार्थों और मनऱ्प्रभावी पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों को एहतियातन हिरासत में रखने का प्रावधान करता है। 'नोट' में कहा गया है कि विधेयक का खंड (बी), पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत प्रदज़् एहतियाती हिरासत के प्रावधान से टकरा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों प्रावधानों के होने से मादक पदार्थ से जुड़ी गतिविधियों के मामले में दो समानांतर एहतियाती हिरासत प्रणालियां कार्यान्वित हो सकती हैं। बयान में संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत संभावित टकराव का प्रश्न भी उठाया गया है।

यह अनुच्छेद टकराव के सिद्धांत से संबंधित है और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच विसंगतियों से संबंधित है। प्रस्तावित कानून और केंद्रीय कानून के बीच दोहराव और टकराव को रोकने के लिए, बयान में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत अपराधों के जिक्र को खंड 2(डी)(3)(बी) से हटाने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 'नोट' की उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी।

अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले निवेश का सिर्फ झूठा प्रचार हुआ

लखनऊ २५/०९ (संवाददाता): समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार निवेश का झूठा प्रचार करती रही और कोई निवेश नहीं हुआ। सपा मुज़्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमई) इकाइयों को बर्बाद कर दिया और निवेशकों ने कोई निवेश नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने करीबियों को आगे बढ़ा रही है। यादव ने भाजपा सरकार पर मोबाइल निर्माण को लेकर भी ''झूठा दावा'' करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में मोबाइल का निर्माण नहीं हो रहा,

बल्कि केवल असेज़्बल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव ''लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव'' है। उन्होंने इसे जनता के लिए अंतिम अवसर बताया। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है तथा संवैधानिक संस्थाओं पर उसने कज़्जा कर लिया है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नोएडा में मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 'इंटरनेशनल ट्रेड शो' की शुरुआत करते हुए सपा पर गंभीर आरोप लगाए थे। शाह ने कहा था कि 2013 में तत्कालीन राज्य सरकार ने दिल्ली में निवेशक सज़्मेलन आयोजित किया था, ज़्योंकि लखनऊ में अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर सज़्मेलन कराने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक कांग्रेस का प्रदर्शन, पटना-चंडीगढ़ में वाटर कैनन से बौछार, हिरासत में कई नेता

नयी दिल्ली २५/०९ (संवाददाता): चुनाव आयोग के कामकाज और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच, शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। वे मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े और उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। जज़्मू-कश्मीर, असम, उज़्राखंड, पश्चिम बंगाल, उज़्र प्रदेश, चंडीगढ़ और मणिपुर समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दज़्तरों की ओर मार्च किया और ष्टश्वष्ट के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की। देहरादून में, उज़्राखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने PCC मुज़्यालय से राज्य सचिवालय स्थित

चुनाव कार्यालय तक मार्च किया ताकि कार्यालय का घेराव किया जा सके। उज़्राखंड PCC अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा राहुल गांधी पिछले तीन सालों से कह रहे हैं कि वोट चोरी के ज़रिए चुनाव आयोग क्चछ्वक्क की सरकारें बनवा रहा है और आज यह बात सच साबित हो गई है। मैं राहुल गांधी की दृढ़ता को सलाम करता हूँ... निश्चित रूप से, इससे देश को फ़ायदा होगा। हम निष्पक्ष और साफ़-सुथरे चुनाव चाहते हैं। अगर साफ़-सुथरे और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो उसका अपना असर होगा।

उज़्राखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने कहा, तीन सालों से राहुल गांधी मुज़्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, ख़ासकर इस बात पर कि कैसे फॉर्म 6 से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई और कैसे स्ढ्ढक्रप्रक्रिया के ज़रिए वोट हटाए या जोड़े गए। हालाँकि, बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने दस महीने की अवधि में 14 बार आपज़्तियाँ उठाईं, लेकिन मुज़्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया। अब यह बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में 13 करोड़ वोट हटा दिए गए और क्चछ्वक्क की केंद्र सरकार ने चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की... उनके ख़िलाफ़ देशद्रोह का आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। लखनऊ में, कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के राज्य कार्यालय में इकट्ठा हुए और स्ढ्ढक्रप्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन किया; साथ ही हज़रतगंज में राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने की भी योजना थी। मणिपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओकराम इबोबी सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता केइशम मेघचंद्र सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमार की गिरज़्तारी और उन पर मुकदमा चलाने की मांग करते हुए लैज़्फेलपट स्थित मुज़्य निर्वाचन कार्यालय की ओर मार्च किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान एक रैली निकाली गई जिसमें ज्ञानेश कुमार की तुरंत गिरज़्तारी के नारे लगाए गए और उनका पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शन हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई; बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके अलावा, जज़्मू में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

विविध समाचार

देशद्रोही हैं ज्ञानेश कुमार, दें इस्तीफा, राहुल गांधी की मांग

नयी दिल्ली २५/०९ (संवाददाता): लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चुनाव प्रणाली पर हमला करने का आरोप लगाते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को लेकर दो चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी - की कथित असहमति का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा से लेकर राज्य विधानसभाओं तक चुनाव में धांधली हो रही है। दो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। मैं भी सवाल पूछता रहा हूं, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश कुमार को पीएम मोदी और शाह ने चुना था। ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ज्ञानेश जी बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं,

लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उन्होंने जो किया है, वह भारत के संविधान पर हमला है।

ज्ञानेश कुमार को देशद्रोही कहते हुए राहुल कुछ पल के लिए रुके और बोले कि ज़्योंकि ये सच हैं। जो व्यक्ति वोट पर हमला करता है, जो भारत के लोकतांत्रिक संस्थान को पूरी तरह से खत्म कर देता है, वह देशद्रोही के अलावा और कुछ नहीं है। आप उसे कोई और नाम नहीं दे सकते। यही सही शज़्द है। उन्होंने कुमार के तुरंत इस्तीफ़े की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि वे ये आरोप हल्के-फुल्के अंदाज़ में नहीं लगा रहे हैं और दावा किया कि वे तीन साल से यह मुद्दा उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी बात अटकलों या कल्पना पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कृपया समझें कि ये दोनों सज्जन ज़्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारत में अब वोट का कोई अस्तित्व नहीं रहा। वे यह भी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को वे भारत में वोट के खत्म होने के लिए ज़िज़्मेदार मानते हैं - यानी श्री ज्ञानेश कुमार - उन्हें भारत के प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया है। उनके सभी पत्रों पर कोई कार्रवाई न होने का कारण यह था कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर उनके संरक्षक या संरक्षक बैठे थे - यानी भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोग जिनकी तस्वीरें हमने आपको यहाँ दिखाई हैं... हम कह रहे हैं कि भारतीय चुनावी प्रणाली की सच्चाई सामने आ गई है, और हमारे पास इतने सबूत हैं कि आपके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा कि मामला यही है। गांधी ने कहा कि हम देश के तौर पर ऐसी स्थिति में हैं जहाँ हम पहले कभी नहीं रहे। 1947 के बाद से हम कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहे, जहाँ हमारे चुनाव बुनियादी तौर पर ही खराब हो चुके हों। संसद द्वारा पारित कानूनों पर सवाल उठाए जा सकते हैं ज़्योंकि वोट खत्म कर दिया गया है, और संस्थाओं पर जो कज़्ज़ा हुआ है, उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत इस स्थिति में है। राहुल गांधी ने हाल के चुनावों में %एंटी-इनकंबेंसी% (मौजूदा सरकार के खिलाफ़ नाराजगी) न दिखने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ, मुझे पता है कि एंटी-इनकंबेंसी कैसे काम करती है।

यह किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ती। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की लड़ाई जीती थी और वे अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थीं, लेकिन दो साल बाद उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन बीजेपी, मोदी और अमित शाह के साथ ऐसा नहीं होता।

कांग्रेस ने तेज की तैयारी, संसद में सीईसी ज्ञानेश कुमार पर आएगा महाभियोग!

नयी दिल्ली २५/०९ (संवाददाता):: विपक्षी पार्टियां संसद के दोनों सदनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस लाएंगी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों से संपर्क किया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, इसे अगले दो हज़्तों के भीतर पेश किया जाएगा। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने चुनाव सूची (इलेज़्टोरल रोल) के प्रबंधन से जुड़े मामले में उन पर कथित आपराधिक आचरण का आरोप लगाया। मोइत्रा ने कहा कि मैं आज भारत के मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आई हूं, जिन्होंने आपराधिक आचरण किया है। मोइत्रा ने आरोप लगाया कि ष्टश्वष्ट ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची बनाए रखने की स्थापित प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया और चुनाव सूची के विशेष गहन संशोधन से जुड़े फैसलों पर सवाल उठाए। उनके ये आरोप चुनाव आयोग की स्ढ्ढक्रप्रक्रिया को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच सामने आए हैं। ञ्जरूष्ट सांसद ने मुज़्य चुनाव आयुक्त को चोर बताते हुए ङ्ग पर लिखा कि ज्ञानेश %चोर% कुमार एक मनमाना काम करने वाले अधिकारी हैं, जिन्होंने बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना काम किया। असली वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। उन्हें कोई छूट नहीं मिल सकती। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है।

भारत के चुनाव आयोग के साथ चल रहे विवाद के बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (ष्टछ्वक्क) ने तीन मुज़्य मांगें रखी हैं। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस राष्ट्रीय दबाव समूह ने मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मुज़्य मांग की। ष्टछ्वक्क के फाउंडर अभिजीत दिपके ने चेतावनी दी है कि अगर कुमार 48 घंटे के भीतर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो ग्रुप विरोध प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही, ग्रुप ने चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (स्ढ्ढक्र) प्रक्रिया को रोकने और आने वाले सभी चुनावों पर रोक लगाने की भी मांग की है। अभिजीत दिपके ने कहा कि कल चुनाव आयोग के बारे में आई एक रिपोर्ट से साबित होता है कि मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। वह देश के सबसे बड़े राष्ट्र-विरोधी हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए... वह भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं... जब से ज्ञानेश कुमार मुज़्य चुनाव आयुक्त बने हैं, सरकार यह तय कर रही है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। ज़्या यही लोकतंत्र है?... कुल मिलाकर, 13 करोड़ से ज़्यादा वोट हटा दिए गए हैं। यह कोई छोटी संज़्या नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष और सज़ाधारी पार्टी (ह्रष्ठ) के बीच का अंतर सिर्फ़ 2न्न था। 13 करोड़ वोट हटाना, कुल वोटों का लगभग 13न्न से 14न्न हिस्सा हटाने के बराबर है। ज़्या ज्ञानेश कुमार जानबूझकर उस 2न्न के अंतर को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वे कभी सज़ा से न हटें? ऐसा ज़्यों किया जा रहा है? इतने सारे वोट हटाने की ज़्या ज़रूरत थी?

समस्तीपुर में सड़क किनारे नाबालिग लड़की से बदसलूकी, वीडियो वायरल होने के बाद 4 गिरफ्तार

समस्तीपुर २५/०९ (संवाददाता): बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बेहद परेशान करने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। जमुई में दो नाबालिगों के साथ हुई सार्वजनिक बदसलूकी के बाद, अब समस्तीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ सड़क किनारे छेड़छाड़ और अभद्रता का मामला उजागर हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार मुज़्य आरोपियों को गिरज़्तार कर लिया है।

यह घटना समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम पुलिस स्टेशन इलाके के जगतसिंहपुर गांव में तटबंध बाईपास रोड पर हुई बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में लड़की को घेरे हुए और उसके साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार और अभद्र टिप्पणी करते हुए देखा गया। जानकारी के मुताबिक, एक नाबालिग लड़का और लड़की मोटरसाइकिल से तटबंध पर पहुंचे थे और बातचीत कर रहे थे, तभी युवकों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। युवकों ने कथित तौर पर लड़के की पिटाई की, जिसके बाद वह मौके से भाग गया।

इसके बाद समूह ने लड़की के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार किया। वायरल फुटेज में लड़की युवकों के व्यवहार का बार-बार विरोध करती दिख रही है। युवकों ने कथित तौर पर कई बार उससे उसका पता पूछा। जब लड़की ने कहा कि वह अपने भाई को बुलाएगी, तो समूह ने उसके भाई के खिलाफ भी अभद्र और गलत भाषा का इस्तेमाल किया।

बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया और बाद में यह फुटेज सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक युवक लड़की को गलत तरीके से छूता और आपज़्िजनक टिप्पणी करता दिख रहा है। लड़की इस व्यवहार का विरोध करती और आपज़्ि जताती दिख रही है। हालांकि, वीडियो की सच्चाई, घटना से जुड़ी पूरी परिस्थितियां और इसमें दिखने वाले सभी लोगों की पहचान और उनकी भूमिका पुलिस जांच का विषय है। वीडियो के कारण समस्तीपुर पुलिस का ध्यान इस घटना की ओर गया, जिसके बाद जांच शुरू की गई।

पुलिस टीमों ने फुटेज में दिखने वाले लोगों की पहचान करने के लिए काम किया। इस मामले में चार लोगों को गिरज़्तार किया गया है और जांच के तहत उनसे पूछताछ की जा रही है।

उनकी पहचान राहुल कुमार (19), अवधेश पासवान (46), विकास शर्मा (32) और रामबाबू साहनी (38) के तौर पर हुई है। समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और स्थानीय पुलिस स्टेशन को स्नढ्ढक्र दर्ज करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर का मामला ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार के जमुई में दो नाबालिगों के कथित उत्पीड़न की एक और घटना ने तथाकथित मॉरल पुलिसिंग और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ व्यवहार को लेकर बहस छेड़ दी है। जमुई मामले की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने तीन लोगों को गिरज़्तार किया है और घटना से कथित तौर पर जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है।

सिक्किम मेंभारी बारिश और भूस्खलन से सड़क संपर्क टूटा

सिक्किम २५/०९ (संवाददाता):हिमालयी राज्य सिक्किम में मौसम के बिगड़े मिजाज ने पर्यटकों और स्थानीय प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार रात से जारी मूसलाधार बारिश के कारण उज़्ारी सिक्किम के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है।

इस प्राकृतिक आपदा के चलते चुंगथांग के पास कम से कम 200 पर्यटक फंस गए हैं। मंगन के जिला कलेज़्टर अनंत जैन ने बताया कि मंगलवार रात चुंगथांग-लाचेन के मुज़्य मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। पत्थरों और मलबे के गिरने से सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई, जिससे लाचेन की ओर जा रहे पर्यटक बीच रास्ते में ही फंस गए। राहत कार्य- फंसे हुए पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें रात भर चुंगथांग में स्थित (भारत-तिज़्बत सीमा पुलिस) कैंप और एक स्थानीय गुरुद्वारे में ठहराया गया। प्रशासन द्वारा उनके भोजन और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है।

जानकारी देते हुए, मंगन डिस्ट्रिज़्ट कलेज़्टर अनंत जैन ने कहा कि लैंडस्लाइड मंगलवार रात को अहम चुंगथांग-लाचेन रूट पर हुआ, जिससे लाचेन जा रहे टूरिस्ट बीच रास्ते में ही फंस गए। उन्होंने कहा कि फंसे हुए विज़िटर्स को रात भर ढ्ढञ्जक्च्क्क कैंप और चुंगथांग के एक गुरुद्वारे में ठहराया गया।अधिकारियों ने कहा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन (क्चक्रह्र) द्वारा रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, और कहा कि अधिकारी स्थिति का रिव्यू करेंगे और मौसम के हालात के आधार पर, रूट्स के सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा की इजाज़त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ टूरिस्ट तब से गंगटोक लौट आए हैं और उन्होंने अपनी यात्रा की योजनाएँ कैंसिल कर दी हैं।इस बीच, लाचुंग जाने वाली सड़क, जो मंगलवार रात को भी ज़्लॉक थी, उसे साफ़ कर दिया गया है.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेज़्नोलॉजी में छात्र की मौत पर न्यायिक जांच की मांग, कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद भारी सुरक्षा तैनात

मुंबई २५/०९ (संवाददाता): मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद, गुरुवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेज़्नोलॉजी बॉज़्बे के मुज़्य गेट के बाहर भारी सुरक्षा इंतज़ाम किए गए और पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए। यह विरोध प्रदर्शन दूसरे साल के छात्र साहिल वाकोडे की दुखद मौत के मामले में जवाबदेही और न्याय की मांग के लिए आयोजित किया गया था। वाकोडे की मौत से जुड़े हालात की पूरी और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग करते हुए, वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्र के परिवार से बात की है और उन्हें पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। राहुल जी ने परिवार से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और साहिल को

न्याय दिलाकर रहेंगे। ढ्ढढ्ढञ्ज बॉज़्बे में यह कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं और हमने पूरी जांच की मांग की थी। हम देख रहे हैं कि शिक्षा का व्यवस्थित रूप से ञ्जस्-करण किया जा रहा है, धार्मिक बंटवारे को बढ़ावा दिया जा रहा है और खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। जब हम यहां सवाल करने आते हैं, तो वे हमें चुप कराने और दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करते हैं। मेरा सवाल है- क्च्छ्वक्क ने शिक्षा व्यवस्था का ज़्या हाल कर दिया है? उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह दुखद घटना एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है और आरोप लगाया कि जाति और धर्म की राजनीति की जा रही है। अहम प्रशासनिक पदों और वाइस-चांसलर की राजनीतिक नियुक्तियों की आलोचना करते हुए गायकवाड़ ने कहा कि इसकी पूरी जांच ज़रूरी है और शिक्षा व्यवस्था पर विचारधारा के इस कज़्ज़े को खत्म करना होगा। वाइस-चांसलर से लेकर अहम प्रशासनिक पदों तक, राजनीतिक नियुक्तियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं। गायकवाड़ ने इस घटना को महज़ आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया; इसके बजाय, उन्होंने इसे बड़े शिक्षण संस्थानों में गहरी जड़ें जमा चुकी जातिवाद, सांप्रदायिकता और विचारधारा के दखल के कारण हुई संस्थागत मौत बताया। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं कि ञ्जस् ने विश्वविद्यालयों और ढ्ढढ्ढञ्ज में घुसपैठ कर ली है और वहां बड़े पैमाने पर जातिवाद और सांप्रदायिकता फैला रही है। हमारी नज़र में, साहिल वाकोडे की दुखद मौत जिसे आत्महत्या कहा जा रहा है। असल में आत्महत्या नहीं है; यह एक संस्थागत मौत है। आज इसके लिए किसी न किसी को ज़िज़्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगर आप विश्वविद्यालयों में छात्र और फैकल्टी के अनुपात को देखें, तो आपको साफ़ तौर पर बड़े पैमाने पर भेदभाव और असमानता दिखाई देगी

सीईसी ज्ञानेश कुमार की बर्खास्गी पर अड़ी कांग्रेस, चंडीगढ़ में पुलिस ने वाटर कैनन से रोका

नयी दिल्ली २५/०९ (संवाददाता): कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुज़्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने व गिरज़्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान चंडीगढ़ स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं। पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता सेज़्टर-17 में प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। कांग्रेस की पंजाब इकाई ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सीईसी कुमार के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे। हालांकि, शुक्रवार को उनकी अनुपस्थिति में वड़िंग ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पूर्व मुज़्यमंत्री एवं जालंधर से मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी भी प्रदर्शन के दौरान मौजूद नहीं रहे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर बढ़ने के लिए पुलिस के अवरोधक को लांघने की कोशिश की तो चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की गई है और नागरिकों से उनके मतदान के अधिकार छीने जा रहे हैं। वड़िंग, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ''वोट चोरी बंद करो'' का नारा लगाते हुए मांग की कि कुमार को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरज़्तार किया जाए। वड़िंग ने कहा, ''इस देश में वोट चोरी हो रही है। भाजपा वोट चोरी करके सरकारें बना रही है। एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा, ''जो चुनावी जीत दिख रही है, वह वास्तव में वोटों की चोरी है।'' वड़िंग ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे बड़े झटके के बाद किसी को भी इन दोनों राज्यों में उसकी जीत की उज़्मीद नहीं थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हेरफेर किया गया था। उन्होंने दोहराया कि पंजाब में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) रद्द किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, राणा गुरजीत सिंह, धर्मवीर गांधी, विजय इंदर सिंगला और बलबीर सिंह सिद्धू सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रंधावा ने कहा कि राहुल गांधी पिछले तीन वर्षों से कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग चुनावों में धांधली करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और निर्वाचन आयोग दोनों देश के नागरिकों के सामने बेनकाब हो चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया था कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उस बात का समर्थन किया है जिसे वह एक साल से अधिक समय से कहते आ रहे हैं कि देश की चुनावी व्यवस्था 卐बर्बाद卐 हो गई है। यह दावा एक अंग्रेजी दैनिक की उस खबर के सामने आने के बाद किया गया जिसमें कहा गया था कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से नाम हटाने और जोड़ने संबंधी मुद्दों पर चिंता जताई थी।

विविध समाचार

'लास्ट मैन इन टावर' में दिव्या दत्ता का किरदार दिखाएगा जिंदगी की उलझी सच्चाई

अभिनेत्री दिव्या दत्ता अपनी आने वाली फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में वह संगीता नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं, जिसकी जिंदगी बाहर से भले ही सामान्य नजर आए लेकिन अंदर से वह कई तरह की परेशानियों, जिम्मेदारियों और भावनात्मक उलझनों से जूझ रही है। अपने इस किरदार को लेकर दिव्या ने कहा कि संगीता कोई असाधारण महिला नही बल्कि हमारे आसपास मौजूद उन तमाम महिलाओं में से एक है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना उलझ जाती हैं कि कई बार अपनी खुशियों और जरूरतों को ही पीछे छोड़ देती हैं।

आईएएनएस से बातचीत में दिव्या दत्ता ने कहा, ''संगीता की जिंदगी पर घर की परिस्थितियों का काफी असर पड़ा है। उसके बच्चे को खास देखभाल की जरूरत है और पति के साथ भी उसकी बातचीत काफी कम है। इन सबके बीच वह खुद भी अपनी जिंदगी और अपने व्यक्तित्व से दूर होती चली गई है। वह अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन एक के बाद एक कई जिम्मेदारिया और परेशानिया उनकी इन कोशिशो में पानी फेर रही है।''

दिव्या ने कहा, ''घर के हालात, बच्चे की जरूरतें और पति के साथ दूरी जैसी चीजों ने उसकी जिंदगी को इस तरह घेर लिया है कि शायद उसे खुद भी एहसास नही हुआ कि वह कब अपने आपको नजरअंदाज करने लगी।''

उन्होंने कहा, ''एक महिला के लिए ये छोटी-छोटी चीजें काफी मायने रखती हैं कि वह कैसे रहती है, खुद को कैसे देखती है, अपनी खुशियों के लिए कितना समय निकालती है... ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा होता है। हालांकि जब रोजमर्रा की जिम्मेदारिया हावी हो जाती हैं तो इंसान धीरे-धीरे उसी जिंदगी को अपनी आदत मान लेता है। संगीता के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वह परेशान है, गुस्सा करती है, कमजोर महसूस करती है लेकिन अपनी इन भावनाओं को खुलकर कहने का उसके पास कोई रास्ता नही है। वह अंदर ही अंदर अपने आप से रोजाना लड़ाई लड़ती है।''

दिव्या ने कहा, ''संगीता के किरदार में एक उम्मीद भी है। वह एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करती है और शायद यही उम्मीद उसे आगे बढ़ाती है।

प्रीति जिंटा ने खोला पेशेवर और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस का राज

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक्टिंग के साथ-साथ अपनी जिंदगी के अलग-अलग किरदारों को भी बखूबी निभाया है। उन्होंने शादी और मां बनने के बाद फिल्मों से दूरी बनाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ बिजनेस पर भी ध्यान दिया। अब लंबे समय बाद फिल्मों में वापसी कर चुकी प्रीति ने अपनी जिंदगी के इस सफर और मां होने के साथ प्रोफेशनल जिम्मेदारिया निभाने को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि करियर और परिवार को एक साथ संभालना आसान नहीं है, लेकिन सही सपोर्ट सिस्टम और सुविधाएं हो तो यह काम काफी हद तक आसान हो जाता है। आईएएनएस से बातचीत में 'सोल्जर' एक्ट्रेस ने कहा कि महिलाएं स्वभाव से ही मल्टीटास्कर होती हैं। उनके मुताबिक, महिलाओं के लिए घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां संभालना कोई नई बात नहीं है। प्रीति ने अपनी मां का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही उनकी मां नौकरी नहीं करती थीं, लेकिन घर और परिवार की देखभाल करना अपने आप में किसी फुल टाइम जॉब से कम नही था।

आईएएनएस से बात करते हुए प्रीति ने कहा, ''महिलाएं स्वभाव से ही मल्टीटास्कर होती हैं। भले ही मेरी मां नौकरी नही करती थीं, लेकिन उनका काम मेरे पिता, तीन बच्चों, घर और न जाने कितनी चीजों की देखभाल करना था। अब महिलाएं सुपर वुमन बन गई हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं काम करती हैं और घर आने के बाद भी बच्चों की देखभाल करती हैं।'' एक्ट्रेस ने कहा, ''काम और मदरहुड को एक साथ संभालना चुनौती भरा जरूर है। मैं खुद को बहुत लकी मानती हू, क्योंकि मेरे साथ ऐसे लोगों का सपोर्ट है, जिनकी मदद से मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिम्मेदारियों को मैनेज कर पाती हू। अगर मुझे मदद नही मिलती, तो मेरे लिए अपने काम के लिए बाहर आना भी मुश्किल होता।''

उन्होंने आगे कहा, ''अगर आप जिंदगी में अलग-अलग चीजें चाहते हैं, तो आपको अलग-अलग समय पर चीजों को प्राथमिकता देनी पड़ती है। जाहिर तौर पर यह आसान नही है, लेकिन अगर आपके पास साधन हैं तो यह इतना मुश्किल भी नही है।''

प्रीति ने कहा, ''जो महिलाएं बिना किसी मदद के नौकरी के साथ घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती हैं, उनके लिए मेरे दिल से बेहद सम्मान है। हर महिला की परिस्थितियां अलग होती हैं और जिन महिलाओं के पास मदद के ज्यादा साधन नहीं हैं, उनके लिए यह सफर और भी चुनौतीपूर्ण होता है। मैं इस बात के लिए भगवान की शुक्रगुजार हू कि मेरे पास अपनी जिंदगी के बारे में कुछ विकल्प चुनने की आजादी है।''

सभी लोगों से खूब मेहनत करवाते हैं अक्षय

अक्षय कुमार के जन्मदिन पर राशि खन्ना ने शेयर किया वीडियो

अक्षय कुमार के जन्मदिन पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस कड़ी में राशि खन्ना ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके साथ बिताए एक मजेदार पल का वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में अक्षय कुमार, विद्या बालन और राशि खन्ना साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अक्षय अपने खास अंदाज में डांस करते दिख रहे हैं और पीछे एक प्राइवेट जेट भी नजर आ रहा है। राशि ने इस वीडियो के साथ अक्षय के लिए एक प्यारा भरा मैसेज भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अभिनेता की मेहनत और उनके मजाकिया अंदाज की तारीफ की। उन्होंने लिखा, ''उस इंसान के नाम, जो अपने आसपास के सभी लोगों से खूब मेहनत करवाते हैं और उससे भी ज्यादा हंसाते हैं। ज्यादा डांस और ज्यादा शरारत करते हैं। जन्मदिन मुबारक हो, अक्षय सर!'' वीडियो में अक्षय, विद्या और राशि, तीनों की मस्ती लोगों को काफी पंसद आ रही है। बता दें कि अक्षय और राशि जल्द ही अनीस बज्मी की आने वाली फैमिली कॉमेडी फिल्म में साथ दिखाई देंगे। फिल्म का नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी स्टारकास्ट ने पहले ही लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। इसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन की जोड़ी भी लंबे समय बाद फिर से साथ नजर आएगी। दोनों को इससे पहले एक साथ 'भूल भुलैया' में देखा गया था और अब एक बार फिर दोनों पर्दे पर साथ आने वाले हैं।

वहीं, अनीस बज्मी के साथ अक्षय की भी लंबे समय बाद वापसी हो रही है। दोनों ने इससे पहले 'वेलकम' में साथ काम किया था और अब करीब 15 साल बाद निर्देशक और अभिनेता की यह जोड़ी दोबारा साथ आई है। इससे पहले अक्षय ने अपने बर्थडे पर आने वाली फिल्म 'हैवान' से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था और उसके साथ जिंदगी को देखने का अपना नजरिया भी बताया। उन्होंने कहा कि हर चीज वैसी नही होती जैसी पहली नजर में दिखाई देती है। कभी जो बुरा नजर आता है, उसके पीछे कोई दूसरी कहानी छिपी हो सकती है और जिसे हम अच्छा समझते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच में वैसा ही हो।

अब तक के किरदारों से काफी अलग है 'हैवान' का किरदार

अक्षय ने फिल्म का वीडियो साझा करते हुए लिखा, ''मेरे जन्मदिन पर एक छोटी-सी बात... जो बुरा दिखाई देता है, वह हमेशा बुरा नहीं होता, और जो अच्छा दिखाई देता है, वह हमेशा अच्छा नहीं होता। शायद यही बात मुझे 'हैवान' ने सिखाई है। इतने सालों से आपने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए शुक्रिया। मैं आपको अपना एक ऐसा रूप दिखाने वाला हू, जिसे आपने पहले नहीं देखा है। प्यार और दुआओं के साथ, आपका अक्षय।'' गौरतलब है कि अक्षय ने अपने फिल्मी करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन 'हैवान' में वह जिस रूप मे नजर आने वाले हैं, वह उनके अब तक के किरदारों से काफी अलग है।

अक्षय खन्ना को रिप्लेस करने पर बोले जयदीप अहलावत

फिल्म 'दृश्यम' के तीसरे भाग 'दृश्यम: द कनक्लूजन' का ट्रेलर गोवा में एक खास इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर ने शिरकत की। इनके अलावा फिल्म में नए किरदार के साथ जुड़े जयदीप अहलावत भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। जयदीप फिल्म में एसपी क्राइम ब्रांच ऑफिसर राजवीर सिंह तोमर के किरदार में नजर आएंगे। वहीं प्रकाश राज भी फिल्म में वकील का किरदार निभाते दिखेंगे। हालांकि वे इस इवेंट में शामिल नहीं हुए। इस फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। यह 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्रेलर लॉन्च के दौरान जयदीप अहलावत से फिल्म में अक्षय खन्ना को रिप्लेस करने को लेकर सवाल किया गया। जयदीप ने साफ किया कि वह अक्षय खन्ना की जगह नहीं आए हैं, बल्कि फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल नया है। जयदीप ने कहा, 'जब मैंने कहानी सुनी थी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं अक्षय की जगह हू। वो किरदार खत्म हुआ है और हमारी जर्नी बिल्कुल नई है। मेरा एकदम नया इंट्रोडक्शन होगा और मीरा और उसकी फैमिली के साथ नया रिलेशनशिप होता है।'

मुझ पर कोई प्रेशर नहीं: जयदीप

अक्षय खन्ना के साथ तुलना को लेकर जयदीप ने कहा कि उन्हें इसे लेकर किसी तरह का दबाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'कोई प्रेशर नहीं था अक्षय के कम्पैरिजन में।

तुलना पर क्या बोले अजय देवगन?

वहीं, अजय देवगन ने भी जयदीप के किरदार को लेकर कहा कि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया, 'पुलिस से केस सॉल्व नहीं हुआ, तो क्राइम ब्रांच से लोग आए हैं। दोनों अलग-अलग किरदार हैं और केस को सॉल्व करने का उनका अप्रोच भी अलग है।' ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म को लेकर अजय देवगन ने कहा कि 'दृश्यम 2' के बाद उन्हें खुद नहीं पता था कि इसकी अगली फिल्म बनेगी या नहीं। उन्होंने कहा, 'हमें नहीं पता था कि 2 के बाद हम बनाएंगे कि नहीं। इतने ट्विस्ट के साथ हम इसे बना पाएंगे या नहीं। हमें लगा कि यही कंक्लूजन है और इसके बाद हमें और कोशिश नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें ट्विस्ट्स हैं और उसी दायरे में रहते हुए कहानी को वहीं से शुरू करना, जहां पिछली कहानी खत्म हुई थी, उसे आगे ले जाना और उतना ही इंटरेस्टिंग बनाना, आई थिंक, रियली इम्पॉसिबल है।'

...अब कैसी फिल्में करना चाहते हैं सैफ अली खान

सुनाया 'हैवान' के सेट पर हुए हादसे का किस्सा

अभिनेता सैफ अली खान सैफ अली खान अब अपने करियर में एक अलग तरह के किरदारों की ओर बढ़ रहे हैं। खास बातचीत में उन्होंने इस बारे में बात की। फिल्म 'हैवान' में वह नेत्रहीन शख्स के किरदार में हैं, जो हालात से लड़ता है, बेबस नहीं है। फिल्म में सस्पेंस, क्राइम और एक्शन है, जबकि अक्षय कुमार उनके सामने नेगेटिव रोल में हैं।

इस फिल्म के लिए हां कहने की सबसे बड़ी वजह क्या थी?

प्रियदर्शन का मुझे इस तरह की स्क्रिप्ट ऑफर करना ही मेरे लिए काफी बड़ी बात थी। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए। मैं कैसी फिल्में करूं? अब मैं चाहता हू कि अजय देवगन जिस तरह की 'दृश्यम' टाइप फिल्में करते हैं, वैसी फिल्में करूं। खासकर थोड़ा मैच्योर होने के बाद मुझे लगा कि यह जॉनर मुझे सूट करेगा। अब मैं 25 साल का नहीं हूं। 'हैवान' में सस्पेंस और थ्रिल है। हीरो अंधा है, लेकिन किसी को बचाने के लिए अपना पूरा दिमाग लगा रहा है। वह हत्या के मामले में फंसता है और उससे निकलने की कोशिश करता है। फिर एक्शन भी है। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि वह सिर्फ बेचारा नहीं है। ऐसे किरदार मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत फैसिनेटिंग होते हैं और मुझे लगता है कि लोग उनसे प्रभावित होते हैं।

यानी इस बार 'बेचारा' दिखना आपके लिए भी नया अनुभव था?

हां, इतना सहानुभूति वाला रोल है कि कभी-कभी दिल से आह निकलती है कि क्या-क्या हो रहा है इसके साथ। ऐसे रोल मुझे ज्यादातर मिलते नहीं हैं। मुझे थोड़े बिगड़े हुए लड़कों के रोल मिलते थे। यह रोल मुझे बहुत आसान लगा और बहुत मजा आया। ऐसे कैरेक्टर में आप बस खड़े हो, थोड़े थके हुए लगो और लोगों के दिल से निकले- 'बेचारा, इसके साथ क्या-क्या हो रहा है।' तो ऐसी और फिल्में होनी चाहिए और ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए। हालांकि उसका बेचारापन उसकी कमजोरी नहीं है। वह टैलेंटेड है। उसकी मां ने उसे संगीत और वायलिन सिखाया है, इसलिए वह म्यूजिक टीचर है। उसके पिता ने उसे मार्शल आर्ट सिखाया है। उसमें एक खास क्षमता भी है, वह इतनी अच्छी तरह सुन सकता है कि हवा में उछली गेंद भी पकड़ सकता है। इसलिए इस किरदार को निभाना मेरे लिए वाकई मजेदार था।

कांच टूटने वाला सीन कितना डरावना था?

वह दिन हमेशा याद रहेगा। एक सीन में पुलिस वाला मुझे पकड़कर कांच के सामने धक्का देने वाला था। हमें कहा गया था कि ज्यादा जोर से नहीं मारना है। लेकिन जोश में वह थोड़ा ज्यादा लग गया और पूरा कांच टूट गया। मैं कांच के सामने गिर गया। बच गया, कैसे पता नहीं। अगर लगता तो बुरी तरह घायल हो सकता था। उस वक्त तो ठीक लगा, क्योंकि शायद खून गरम था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैंने बहुत जान लगा दी थी और दो दिन आराम करना पड़ा। अक्षय के साथ भी फाइट है, लेकिन पुलिस स्टेशन वाला एक्शन मुझे ज्यादा पसंद आया।

उम्र बढ़ने के साथ ऐसे एक्शन को लेकर डर बढ़ता है?

एक्शन करना और एक उम्र के बाद एक्शन करना बहुत मेहनत वाला काम है। बॉलीवुड खासकर बहुत मेहनत करवाता है, क्योंकि हम अपने खुद के स्टंट्स करते हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे आप 25 साल के हैं। मैंने हमेशा एक्शन किया है। बचपन में इतना कन्विन्सिंग नहीं होता था, लेकिन धीरे-धीरे और कन्विन्सिंग हो गया और मुझे एक्शन पसंद है। हालांकि सबके लिए यह आसान नहीं है। काफी एक्टर्स हैं जिनके घुटने साथ नहीं दे रहे, किसी का कंधा साथ नहीं दे रहा।

ओटीटी ने भी आपको कई तरह के किरदार दिए

सीरीज में ज्यादा वक्त मिलता है और एक्टर को खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। कैरेक्टर को इतने वक्त दे रहे हो और इतने टाइम के लिए उस लुक और कैरेक्टर में जुड़े रहते हो। जैसे 'सेक्रेड गेम्स' में इतनी शूटिंग की कि एक सीजन के बाद मुझे लगा कि उस रोल में मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि इतने दिन से वो रोल प्ले कर रहे थे। किरदार बस जाता है। मैं नहीं मानता कि छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन से कुछ कम है। हर फ्रेम कुछ एक्सप्रेस करने का मौका है। कुछ स्टार्स बोलते हैं कि ओटीटी या फिल्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दोनों कर सकते हैं तो ग्रेट।

कलिंग समाचार

संपादकीय

दो दिन में दो भाषण, फिर भी कुछ साफ नहीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित किया। वीर रस से सराबोर इस संबोधन में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर नए सवाल खड़े हो गए। इन सवालों को विपक्ष ने पूछना शुरु किया ही था कि मंगलवार को सुबह पहले नरेन्द्र मोदी अचानक पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंच गए और फिर दोपहर तक उनका एक और वीर रस में पगा हुआ भाषण सामने आ गया। शनिवार रात शाहबाज शरीफ ने भी इसी तरह का भाषण पाकिस्तान के लोगों को सुनाया था। इन भाषणों को सुनकर न जाने क्यों चाबी वाले खिलौनों का याल आता है, जिसमें चाबी भर दो तो वह तब तक चलता रहता है, जब तक चाबी पूरी तरह से उल्टी न घूम जाए। चाबी भरने वाले हाथ दिखाई नहीं देते, केवल खिलौने चलते दिखते हैं। खैर..मंगलवार सैनिकों के बीच पहुंचकर श्री मोदी ने अच्छा ही किया। जो लोग जान हथेली पर लेकर देश की रक्षा करते हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो किया जाए, सो कम है। आदमपुर एयरबेस से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें अनकहा संदेश भी पाकिस्तान के लिए था। इनमें मोदी के साथ पार्श्व में मिग-29 और एस-400 भी दिखाई दिए। जबकि पाकिस्तान का दावा था कि उसने आदमपुर में एस-400 वायुरक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है। यहां सैनिकों को संबोधित करते हुए भी श्री मोदी ने पाकिस्तान को कहा कि निर्दोषों का खून बहाने का एक ही अंजाम है, महाविनाश। अभी सैन्य कार्रवाई सिर्फ स्थगित की है, फिर से दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। कुछ ऐसी ही बात सोमवार के संबोधन में भी थी। तब श्री मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिफ़ स्थगित हुआ है. आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि वो क्या रवैया अपनाता है। अब सवाल उठता है कि अगर अब भी वार-प्रतिवार की आशंका है, तो फिर युद्धविराम की बात कहां से आई, क्यों श्री मोदी इसका खुलकर खंडन नहीं कर रहे। क्या ये समय शाब्दिक जाल फैलाने का है कि सैन्य आपरेशन अभी स्थगित हुआ है। इसका क्या मतलब है, प्रधानमंत्री साफ-साफ बतलाएं कि अभी हम युद्ध में हैं या नहीं हैं। हम पाकिस्तान के अगले कदम या उसके दुस्साहस का इंतजार क्यों कर रहे हैं। क्या पहलगाम के बाद भी हमारे जो जवान शहीद हुए, बेकसूर नागरिक मारे गए, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से भी युद्धविराम की घोषणा के बाद हमारे सीमांत इलाकों में ड्रोन मंडराते हुए देखे गए हैं, तो क्या इसे पाकिस्तान का दुस्साहस ही नहीं समझा जाना चाहिए। इस संकट की घड़ी में भी अगर प्रधानमंत्री साफगोई से सारी बातें नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे। जब नोटबंदी या लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, तब भी कई गोल-मोल बातें और दावे सरकार ने किए थे। उन पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए लेकिन किसी का जवाब देना जरूरी नहीं समझा गया। चलिए वो देश के आंतरिक मामले थे और जनता ने कुछ अच्छा होने की उ मीद में तब के कष्टों को सहन कर लिया। लेकिन इस बार तो आम जनता की सुरक्षा और देश की प्रतिष्ठा दोनों दांव पर लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के संदर्भ में मनमाने बयान दे रहे हैं। युद्ध विराम के ऐलान के बाद नए बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार की वजह से ये संघर्ष विराम किया है। पाकिस्तान अपनी जाने कि उसने किस दबाव में संघर्ष विराम मंजूर किया, लेकिन भारत इसके लिए राजी क्यों हुआ, ये बात नरेन्द्र मोदी को अपने संबोधन में बतानी चाहिए थी। क्या ट्रंप अब भारत के आधिकारिक प्रवक्ता हो गए हैं कि वो जो बयान देंगे, दुनिया उसे भारत का बयान मानेगी, क्योंकि ट्रंप की किसी बात को अब तक श्री मोदी ने या उनकी सरकार ने खारिज नहीं किया है। सोमवार के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक गंभीर बात कही कि %भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। परमाणु ब्लैकमेल के तहत चलने वाले आतंकी ढांचे भारत के निशाने पर होंगे। ध्यान रहे कि ब्लैकमेल एक गंभीर शब्द और बड़ा आरोप है, खासकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में।

आतंकवाद के खिलाफ एकता और भाजपा का पाखंड

राजेंद्र शर्मा

विदेश सेवा के अधिकारियों के मुकाबले, इन सांसदों/ राजनीतिक नेताओं का वजन विदेशी मोर्चे पर भी इसीलिए अधिक माना जा रहा है कि वे अपनी राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारतीय जनता की राय का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की आंतरिक दिक्कतों का फायदा उठाने की कोशिश में, मोदी सरकार ने इन मिशनों के भेजे जाने के पूरे विचार में ही पलीता लगा दिया है।

मैं यह देखकर प्रसन्न हूं कि कई दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें उतनी ही शिद्दत से यह मांग भी करनी चाहिए कि भीड़ हिंसा के शिकार, बिना कानूनी प्रक्रिया के मकानों पर बुलडोजर चलवाए जाने और भाजपा की नफरत की राजनीति के शिकार अन्य लोगों को भी, समान रूप से एक भारतीय नागरिक के रूप में न्याय और सुरक्षा दी जाए।दो महिला अफसरों का प्रेस कान्फ्रेंस करना दीखने में एक महत्वपूर्ण दृश्य हो सकता है, लेकिन जब तक यह नजारा जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव में तब्दील न हो, तब तक यह केवल एक %दृश्य राजनीति% (ऑप्टिक्स) ही रहेगा—एक छलावा।%

अशोका विश्वविद्यालय के इतिहास तथा राजनीति विभाग के प्रोफेसर तथा राजनीति विभाग के विभागाध्यक्ष, प्रो. अली खान महमूदाबाद की ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित अपेक्षाकृत लंबी फेसबुक पोस्ट की शायद यही पंक्तियां हैं, जिनके लिए न सिर्फ उनको हड़बड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा गिर तार किया गया है, उन्हें अन्य अनेक धाराओं के अलावा राजद्रोह के दो-दो आरोपों में गिर तार किया गया है। हजारों की सं या में अकादमिकों और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर अली खान की गिर तारी को सरासर अनुचित तथा मनमानी बताते हुए, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन बताने के साथ ही, जिस तरह कुछ विस्तार से उनकी टिप्पणी में कुछ भी, किसी भी नजर से आपत्तिजनक होने मात्र का खंडन किया है, उससे पूरी तरह से सहमत होने के चलते, हम यहां उसे दोहराना आवश्यक नहीं समझते हैं। हम यहां सिर्फ इतना ध्यान दिलाना चाहेंगे कि प्रो. अली इस टिप्पणी में जिस छलावे या पाखंड से बचे जाने का ताकाजा कर रहे थे, उनकी गिर तारी आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्र को एकजुट करने के इस चुनौतीपूर्ण समय में भी सत्ताधारी संघ-भाजपा के उसी पाखंड का सहारा लेने का, एक और सबूत पेश कर रही थी।

प्रो. अली की गिर तारी इस पाखंड को इसलिए और किसी उदाहरण से ज्यादा मुखरता से उजागर करती है कि ठीक इसी समय पर, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, कुंवर विजय शाह के मामले में, उसी संघ-भाजपा की सरकार, इससे ठीक उल्टा ही आचरण प्रदर्शित कर रही थी। प्रो. अली के विपरीत, भाजपायी मंत्री के खिलाफ, किसी भी नजर से क्यों न देखा जाए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सचेत रूप से भारतीय कार्रवाई का चेहरा बनायी गयी, कर्नल सोफिया कुरैशी के घनघोर अपमान का मामला बनता है। और शुद्ध सांप्रदायिक आधार पर यानी उनके मुसलमान होने के लिए ही, उनका ऐसा अपमान करने का मामला बनता है। इसके बावजूद, जैसा कि सभी जानते हैं भाजपायी मंत्री के खिलाफ, न तो भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई करने की जरूरत समझी और न ही संघ-भाजपा परिवार ने।

यहां तक कि इस मामले पर चारों ओर शोर मचने के बाद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बैंच ने स्वतः संज्ञान लेकर, मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बहुत ही स त आदेश भी जारी कर दिए। इसके बाद मजबूरी में आखिरी घंटे पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो की लेकिन, इतनी लचर एफआईआर कि हाई कोर्ट की बैंच को अगले दिन फिर से सरकार को सिर्फ फटकार ही नहीं लगानी पड़ी, यह आदेश भी जारी करना पड़ा कि आगे अदालत इस मामले की निगरानी करेगी। इसके बाद भी, भाजपायी राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि वह दोषी मंत्री की गिर तारी नहीं करने जा रही है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विजय शाह की गिर तारी की किसी भी संभावना से इंकार ठीक उस समय किया जा रहा था, जब उसी संघ-भाजपा की हरियाणा सरकार, प्रो. अली खान की दिल्ली से गिर तारी की तैयारी कर रही थी।

बेशक, पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्याएं की थीं। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार की ओर से एक पत्रकार वार्ता में, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने रेखांकित भी किया था, इसके पीछे आतंकवादियों का मकसद देश में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना था। उनका यह कहना भी बहुत हद तक सही था कि देश ने, आतंकवादियों के इन मंसूबों को विफल कर दिया था। पर बहुत हद तक ही। बेशक, आतंकवादियों की इस दरिंदगी के खिलाफ आम तौर पर पूरा देश एकजुट था। ज मू-कश्मीर ने और देश के अल्पसं यकों ने खासतौर पर, इस दरिंदगी के लिए अपने नाम के इस्तेमाल को बलपूर्वक ठुकराया था। देश व जनता की इस व्यापक एकता की अभिव्यक्ति, सर्वदलीय बैठक के जरिए आतंकवाद और उसके प्रश्रयदाताओं के खिलाफ, पूरी तरह से एकजुट संदेश में भी हुई थी। लेकिन, इसके समानांतर एक क्षीण किंतु सत्तातंत्र का संरक्षण प्राप्त होने से उग्र धारा, विभाजन पैदा करने की भी थी। यह धारा, आतंकवादियों की करतूतों के बहाने से खासतौर पर कश्मीरी मुसलमानों को और आम तौर पर मुस्लिम अल्पसं यकों को हमलों का निशाना बनाए जाने की थी। जाहिर है कि भौतिक हमलों से कई गुना बड़ा था, वैचारिक-भावनात्मक हमलों का दायरा, और ये हमले सत्ता परिवार के आईटी सेल द्वारा संचालित ताने-बाने के जरिए किए जा रहे थे।

बहरहाल, शासन की ओर से किसी रोक-टोक के अभाव में भौतिक हमलों का सिलसिला भी, आपरेशन सिंदूर के शुरू होने तक जारी ही था। एसोसिएशन ऑफ प्रोटैक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) द्वारा 22 अप्रैल से 8 मई के बीच, देश के 20 राज्यों में 180 से ज्यादा सांप्रदायिक घटनाओं का जो विवरण एकत्रित किया गया है, उसके अनुसार इनमें 106 घटनाएं पहलगाम के आतंकवादी हमले से संबंधित थीं और इनकी चपेट में कम से कम 316 लोग आए थे। इनमें 39 हमले की, 19 तोड़-फोड़ की और 42 मुसलमानों को तंग किए जाने की घटनाएं थीं। यह दिखाता है कि जब देश को एकता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस घड़ी में भी सत्ताधारी संघ-भाजपा तथा उनके शासन द्वारा संरक्षित हिंदुत्ववादी ताकतें, जनता की एकता की ही जड़ों को खोखला करने में लगी हुई थीं और शासन की एकता की गुहारों को पाखंड में तब्दील करने में लगी हुई थीं।

आतंकवाद के विरुद्ध देश और देशवासियों की सहज-स्वाभाविक एकता के लिए, अपने विभाजनकारी व्यवहार से चुनौती खड़ी करने का मोदी सरकार का खेल %आपरेशन सिंदूर% के नाम से पाकिस्तान के साथ चार दिन की सैन्य मुठभेड़ के बाद भी थमा नहीं है। बेशक, इस पूरे प्रकरण में भारत के विदेश नीति तंत्र का प्रदर्शन सत्यानाशी रहा है। इसका सबसे प्रत्यक्ष सबूत तब मिल गया, जबकि इन झड़पों के बीच, पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी जगत का ही बोलबाला है, एक अरब डालर से ज्यादा के ऋण के लिए मंजूरी दे दी। आईएमएफ के कुल 25 से ज्यादा सदस्यों के बोर्ड में, भारत के सिवा एक भी देश नहीं था, जो इस ऋण की मंजूरी के खिलाफ होता। यहां तक कि अंततः भारत ने भी इस आधार पर इस फैसले का विरोध करने की जगह, निर्णय से खुद को अलग रखने का ही रास्ता अपनाया, कि उसके मत का जितना वजन था, उसके आधार पर विरोध करने का विकल्प ही नहीं था। यहां भारत ही एक प्रकार से पूरी तरह से अलग-थलग नजर आया।

यह इसके ऊपर से था कि सैन्य टकराव के दौरान भी भारत, इसी तरह अलग-थलग नजर आया था। यह मोदी राज की ग्यारह साल की विदेश नीति का ही कुल हासिल है कि भारत ने चुनौती के इस समय में, खुद को दुनिया में अलग-थलग पाया है। यह विदेश नीति, स्वतंत्रता के बाद से भारत को जिन-जिन चीजों के लिए जाना गया था, उसकी कमजोर की पक्षधरता से लेकर जनतांत्रिकता, धर्मनिरपेक्षता तक की पहचान के पलटे जाने की ही विदेश नीति रही है, बहरहाल उस पर फिर कभी।

विदेशी मोर्चे की इन सच्चाइयों के सामने, सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री की वाचाल अनुपस्थिति के बाद भी और संसद का विशेष सत्र बुलाने से भी इंकार कर के, मोदी सरकार के देश में राजनीतिक राय की एकता को यथासंभव मुश्किल बनाने के बाद भी, सरकार ने जब आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए और इस मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, करीब तीन दर्जन राजधानियों में, सात बहुपक्षीय राजनीतिक-कूटनीतिक मिशन भेजने का फैसला लिया, विपक्ष ने बिना किसी खास अगर-मगर के इसका समर्थन किया। लेकिन, मोदी राज के विभाजनप्रेमी मिजाज ने, इसे भी क्षुद्र राजनीतिक तिकड़म का मैदान बना लिया। पहले राजनीतिक पार्टियों से इस मिशन में शामिल करने के लिए प्रतिनिधियों से नाम मांगे गए। लेकिन, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, कांग्रेस ने जब मांगे गए चार नाम दिए, मोदी सरकार ने इन चार नामों में से एक को छोड़कर, सभी नामों को नामंजूर कर दिया और अपनी मर्जी के कांग्रेस नेताओं के नाम प्रतिनिधिमंडलों में जोड़ दिए।

इस तरह, इन प्रतिनिधिमंडलों के देश छोड़ने से पहले ही, सरकार ने खुद ही इसके दावों पर प्रश्न खड़े करा दिए कि इन मिशनों के जरिए, आतंकवाद और पाकिस्तान के मुद्दे पर पूरा भारत, एक स्वर से बोल रहा होगा। विपक्षी पार्टियों द्वारा भले ही इसे बहुत बड़ा मुद्दा न बनाया जा रहा हो, लेकिन इतना तय है कि अब सरकार द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि, अपनी पार्टियों से ज्यादा सरकार का ही प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे और उसी हद तक देश की राजनीतिक राय की एकता का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ होंगे। शासक पार्टी की ओर से इस सिलसिले में और सबसे बढ़कर शशि थरूर के शामिल किए जाने के लिए, %योग्यता% या %उपयुक्तता% का जो तर्क उछाला गया है और भी बेढब है। इन प्रतिनिधिमंडलों में सबसे प्रमुखता से राजनीतिक नेताओं को जो शामिल किया जा रहा है, कम से कम विदेश सेवा के अधिकारियों के मुकाबले बेहतर भाषायी कौशल के लिए तो नहीं ही शामिल किया जा रहा है। विदेश सेवा के अधिकारियों के मुकाबले, इन सांसदों/ राजनीतिक नेताओं का वजन विदेशी मोर्चे पर भी इसीलिए अधिक माना जा रहा है कि वे अपनी राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारतीय जनता की राय का प्रतिनिधित्व करती हैं।

मोदी सरकार प्रेस को दबाकर पाकिस्तान की चुनौती का सामना नहीं कर सकती

सुशील कुट्टी

शाह के समर्थकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस महीने की शुरुआत में, गुजरात समाचार के आधिकारिक %एक्स% अकाउंट को बिना किसी कारण बताये बंद कर दिया गया था। धोखाधड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तथाकथित मोदी विरोधी मीडिया मोदी सरकार के प्रतिशोध से बच नहीं पाया है। नवीनतम %पीड़ितों% में %द वायर% भी शामिल है, जिसे %ब्लॉक% कर दिया गया था।

अगर आप उन्हें चुप नहीं करा सकते, तो उनको चुप करा दें!% मोदी के भारत में यही कहावत है। %उनको चुप करा दें% का मतलब है, बोली और लिखी गयी आवाज़ को दबा दें। %उन्हें चुप करा दें% का मतलब है, उनको सलाखों के पीछे बंद कर दें, जो परेशान कर रहे हैं, और नियंत्रण में नहीं हैं । इसके %क्यों% के जवाब के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है! इतना ही काफी है कि वह व्यक्ति सत्ता के लिए एक स्पष्ट और मौजूदा ख़तरा है।इस समय, खबरों में दो %शाह% हैं। मध्य प्रदेश के शाह और गुजरात समाचार के शाह। मध्य प्रदेश के शाह ने सेना के एक %हीरो% के खिलाफ़ उपहास और दुर्भावना से भरे शब्द कहे और गुजरात समाचार के शाह ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के शाह एक आज़ाद पक्षी हैं। 73 वर्षीय गुजरात के शाह प्रवर्तन निदेशालय की सबसे बड़ी दुर्भावना के निशाने पर हैं!अलग-अलग शाहों के लिए अलग-अलग चालें! एक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें गिर तारी और कारावास से छूट है। दूसरे हर मायने में %बाहुबली% हैं, जिनकी कलम तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है और इसलिए उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के विचार में चुप करा दिया जाना चाहिए।

बाहुबली शाह और मध्य प्रदेश के शाह के साथ किये गये व्यवहार की तुलना करें तो भेदभाव विशाल पेड़ की तरह खड़ा है। उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के शाह के खिलाफ़ स्वतः संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज की गयी। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचा। मध्य प्रदेश के शाह खुलेआम घूम रहे मानो बेदाग हों। लेकिन 15 मई की देर रात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात के %गुजरात समाचार% के मालिक बाहुबली शाह को वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिर तार कर लिया। प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले लोग, जिनसे मोदी सरकार सहमत नहीं है, बाहुबली शाह के साथ एकजुटता में सामने आये हैं।

ऐसे समय में हुई है जब देश में युद्ध चल रहा है। स्वतंत्र मीडिया बाहुबली शाह की ईडी द्वारा की गयी गिर तारी को %अपराध% कहता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन विमेंस प्रेस कोर, प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, सभी ने बाहुबली शाह की ईडी द्वारा की गयी गिर तारी की निंदा की है।

बाहुबली शांतिलाल शाह लोक प्रकाशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, जो गुजरात समाचार% प्रकाशित करता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात से प्रकाशित होने वाला एक व्यापक रूप से प्रसारित दैनिक है।गुजरात की एक अदालत ने 16 मई को बाहुबली शाह को अंतरिम जमानत दे दी। ईडी 2016 से बाहुबली शाह का पीछा कर रहा है। 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कथित तौर पर धन के दुरुपयोग के लिए जांच शुरू की थी। इस बार भी ईडी ने लोक प्रकाशन के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। आयकर (आई-टी) विभाग ने भी मुंबई, वडोदरा और अहमदाबाद में एक साथ छापेमारी की। शाह के समर्थकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस महीने की शुरुआत में, गुजरात समाचार के आधिकारिक %एक्स% अकाउंट को बिना किसी कारण बताये बंद कर दिया गया था। धोखाधड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तथाकथित मोदी विरोधी मीडिया मोदी सरकार के प्रतिशोध से बच नहीं पाया है। नवीनतम %पीड़ितों% में %द वायर% भी शामिल है, जिसे %ब्लॉक% कर दिया गया था।

यह तो पता नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को %गुजरात समाचार ने कब और कैसे निशाना बनाया या बदनाम किया, लेकिन विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को यकीन है कि %गुजरात समाचार% को सत्ता के सामने सच बोलने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि %डराने की राजनीति% अब मोदी सरकार की %पहचान% बन गयी है।

मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। गुजरात समाचार 93 साल पुराना संगठन है। मोदी ने साबित कर दिया है कि आलोचकों को गिर तार करना डरे हुए तानाशाह की पहली निशानी है! जो कोई भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठायेगा या भाजपा के साथ समझौता नहीं करेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा, %कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह गुजरात समाचार को खामोश करने और न केवल एक अखबार, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश है।बाहुबली शाह को खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गयी। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि गुजरात समाचार हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा है और भारत-पाकिस्तान युद्ध से निपटने के मामले में सरकार के तौर-तरीकों सहित %भाजपा सरकार और पीएम मोदी को आईना दिखाता रहा है%। बाहुबली शाह के एक रिश्तेदार ने कहा, %हमें नहीं पता कि वे हमारे साथ अंडरवर्ल्ड के लोगों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं... इतने सालों के बाद अचानक क्या हो गया? गुजरात समाचार 97 साल पुराना है और इसे गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पढ़ा जाता है। गुजरात समाचार वेबसाइट की औसत दैनिक पाठक सं या 46 लाख है, लेकिन जब %ऑपरेशन सिंदूर% शुरू किया गया, तो गुजरात समाचार के %एक्स% हैंडल को निलंबित कर दिया गया! ईडी का कहना है कि %शाह से हिरासत में पूछताछ जरूरी है% और बाहुबली शाह के रिश्तेदार कांग्रेस के शब्दों को दोहराते हैं: आलोचकों को गिर तार करना एक डरे हुए तानाशाह का पहला संकेत है। फिलहाल, बाहुबली शांतिलाल शाह को अंतरिम जमानत मिल गयी है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई एक %डरे हुए तानाशाह% हैं, तो उनकी मुश्किलें अभी शुरू ही हुई हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठायेगा और %बीजेपी से समझौता% नहीं करेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। बाहुबली शाह को इस नियति से बचने के लिए नियमित जमानत लेनी होगी। वह मध्य प्रदेश के शाह नहीं, बल्कि गुजरात समाचार शाह हैं!

विविध समाचार

युवाओं को विदेशों में सुरक्षित रोजगार से जोड़ेगी हिमाचल सरकार : उप–मुख्यमंत्री

शिमला। उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल सरकार युवाओं को विदेशों में सुरक्षित रोजगार से जोड़ेगी। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक पहल की है कि हमारे युवाओं को विदेशों में सुरक्षित, कानूनी और भरोसेमंद माध्यमों से रोजगार मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं जिम्मेदारी लेकर युवाओं को विदेश भेजने की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बना रही है, ताकि किसी को भी ठगी, धोखे या असुरक्षा की स्थिति का सामना न करना पड़े। यह कदम प्रदेश सरकार की 'हर युवा को हुनर, हर हुनर को अवसर' की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उप–मुख्यमंत्री सोमवार को पालकवाह में आयोजित हिमाचल सरकार की 'ओवरसीज रिक्रूटमेंट ड्राइव' की श्रृंखला के राज्यस्तरीय कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और यह पहल उसी दिशा में एक ठोस कदम है। विदेशों में उपलब्ध विभिन्न ट्रेड्स में नौकरियों की मांग के अनुसार युवाओं का चयन किया जाएगा, ताकि कौशल और अवसर का सही समन्वय सुनिश्चित हो सके। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी होती थी। माता–पिता अपने जीवन की गाढ़ी कमाई खर्च कर बच्चों को बाहर भेजते थे, पर अवैध तरीके और जालसाजी से ठगे जाते थे। अब हिमाचल सरकार ने तय किया है कि युवाओं को सुलभ, सस्ते और कानूनी तरीके से विदेश भेजा जाएगा। उप–मुख्यमंत्री ने कहा यह सरकार का सबसे सुरक्षित, कानूनी और पारदर्शी तरीका है, जिससे हिमाचल के युवा अपने कौशल के अनुरूप विदेश में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। विदेशों में स्किल की मांग है और हिमाचल प्रदेश के युवा इससे लाभान्वित होंगे। इस पहल से रोजगार कार्यालय की कार्यप्रणाली में नवाचार आएगा और युवाओं को हर संभव सहायता मिलेगी। श्री अग्निहोत्री ने विभाग से इस अभियान को और विस्तारित करने तथा युवाओं की हर संभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने युवाओं से ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने और डेटा सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने चार चयनित युवाओं को प्रोविजनल ऑफर लेटर भी प्रदान किए। यह कार्यक्रम श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। यह इस कड़ी का दूसरा आयोजन था जिसकी 9 अक्तूबर को हमीरपुर से शुरूआत की गई थी। पालकवाह में ट्रेलर चालक के 100 पदों के लिए प्रदेश के 457 युवाओं ने भाग लिया। अभ्यर्थियों की अंग्रेजी कौशल क्षमता का परीक्षण पालकवाह सभागार परिसर एवं ड्राइविंग टेस्ट कांगड़ मैदान में लिया गया। चयनित अभ्यर्थियों को दुबई के जेबेल अली पोर्ट में नियुक्ति मिलेगी। उन्हें 2,250 यूएई दिरहम (लगभग 52,000 रुपये) मासिक वेतन, आवास, ओवरटाइम और अन्य भत्तों की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि यह पहली बार है जब प्रदेश सरकार ने युवाओं को विदेश भेजने के लिए औपचारिक नीति बनाई है। विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार युवाओं को बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विदेश में भेजे जाने वाले युवाओं को कोई कठिनाई या ठगी का सामना न करना पड़े। इसके लिए समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की जा रही है।

राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम एक सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहा है, जिससे युवा अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे साझा कर सकेंगे। इस अवसर पर जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में अभ्यार्थी और स्थानीय युवा उपस्थित रहे।

पंजाब में इमारतों की ऊंचाई 15 से बढ़ाकर 21 मीटर तक करने के लिए अब मंजूरी की जरूरत नहीं

चंडीगढ : मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने बरनाला नगर कौंसिल को अपग्रेड करते हुए नगर निगम का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, लुधियाना जिले में 'लुधियाना नॉर्थ' नाम से एक नई सब–तहसील बनाने के लिए भी जरूरी मंजूरी दे दी गई है। पंजाब कैबिनेट ने 'पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग नियम 2025' को भी हरी झंडी दे दी है। इस नए नियम के मुताबिक, पंजाब में बनने वाली नई कॉलोनियों में इमारतों की ऊंचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर तक करने के लिए अब विभाग से अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए केवल आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने 'पंजाब स्पोर्ट्स मेडिसिन काडर' में लगभग 100 नई असामियां (पद) भरने की भी मंजूरी दी है। ये सभी भर्तियां तीन साल के लिए ठेके के आधार पर की जाएंगी। इनमें ग्रुप ए की 14, ग्रुप बी की 16 और ग्रुप सी की लगभग 80 असामियां भरी जाएंगी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा डेरा बस्सी में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनाने के लिए 4 एकड़ जमीन मुहैया कराने की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में भी संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति केंद्रों में दी जाने वाली दवाइयों की देखरेख और प्रबंधन अब सीधे पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा।

आप विधायक लालपुरा को हाईकोर्ट से झटका, सजा पर नहीं लगेगी रोक

चंडीगढ :पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से आज आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को करारा झटका लगा है। विधायक ने खुद को हुई चार साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा पर रोक से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, इसलिए इस समय तत्काल हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं लगती। विधायक लालपुरा के वकील ने दलील दी कि अगर सजा पर रोक नहीं लगाई गई, तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाएगी, जिसके लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब रद्द करने जैसे कदम उठाए ही नहीं गए, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले महीने के लिए स्थगित कर दी और राज्य सरकार को अगली तारीख पर पूरे मामले का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।

अकाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज कर आप ने अपनी हार स्वीकार की : हरसिमरत कौर बादल

तरनतारण। वरिष्ठ अकाली नेता सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी ने तरनतारण उपचुनाव में अकाली दल के उम्मीदवार की बेटी कंचनप्रीत कौर और अन्य अकाली नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर अपनी हार स्वीकार कर ली है।

यहां पार्टी उम्मीदवार प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लोगों से अपील की कि वे "धर्मी फौजी" के परिवार का समर्थन करें, जो समाज सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित है। वहीं दूसरी ओर "गद्दार" और आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू है, जो प्रचार वाली गाड़ियों से लटककर सत्ता में आने का सपना देख रहा है। अकाली नेता ने जोर देकर कहा कि दिल्ली आधारित सभी पार्टियाँ एकजुट होकर अकाली दल के खिलाफ खड़ी हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन कर पंजाब विरोधी ताकतों को स्पष्ट संदेश दें, जो अपने स्वार्थी राजनीतिक हितों के लिए पंजाबियों को बाँटने पर तुली हुई हैं।

उन्होंने कहा, "मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप चुनाव लड़ रही सभी पार्टियों का मूल्यांकन करें। आपने देखा है कि पिछली कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के अपने वादे से मुकर गई।

आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को मुआवजा और युवाओं को रोजगार देने से इनकार कर चुकी है, जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति आपके सामने है।" हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि तरनतारण उपचुनाव की लड़ाई सच और झूठ के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लगातार जनता के साथ धोखा किया है। हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान भी इनमें से कोई पार्टी जनता की मदद के लिए नहीं उतरी।

उन्होंने कहा कि सिर्फ अकाली दल ही किसानों की सहायता के लिए आगे आया और एक लाख एकड़ भूमि के लिए प्रमाणित गेहूं के बीज उपलब्ध करवा रहा है। बठिंडा की सांसद ने यह भी बताया कि किस तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब की महिलाओं से झूठे वादे किए और फिर उन्हें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों से कहें कि वे वोट मांगने से पहले उनके खातों में ध45,000 जमा करवाएं, क्योंकि उन्होंने चार साल पहले ध1,000 प्रति माह देने का वादा किया था। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अकाली दल ने अपनी सरकार के समय सीमावर्ती क्षेत्र में अनेक विकास योजनाएँ लागू की थीं। पार्टी ने ही बार्डर फेंस के पार खेती करने वाले किसानों को मुआवजा दिया था।

उसी ने लिंक सड़कों का जाल बिछाया, मंडियाँ बनवाईं और आटा–दाल, बुजुर्ग पेंशन व शगुन जैसी समाज कल्याण योजनाएँ शुरू कीं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इन सभी योजनाओं को या तो बंद कर दिया है या इनमें भारी कटौती कर दी है, जिससे समाज के गरीब और वंचित वर्ग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस मौके पर वरिष्ठ नेता गुरचरण सिंह ग्रेवाल, बीबी कंचनप्रीत कौर, परमबंस सिंह रोमाणा, गौरव वल्टोहा, परमजीत ढिल्लों, मक्खन लालका, गुरसेवक सिंह शेख और गगनदीप सिंह खंडेबाद मौजूद थे।

समाजवादी आंदोलन के जनक आचार्य नरेंद्रदेव

भारतीय समाजवादी आंदोलन के तीन प्रमुख स्तम्भ आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ. राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण ने समाजवाद की जड़ों को भारत में गहराई तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाई। इनकी अमिट छाप जनमानस पर ऐसी पड़ी कि भले ही आज समाजवादी आंदोलन के संगठन एकजुट नहीं हैं फिर भी इन नेताओं की व्यक्तिगत ऊर्जा समय–समय पर समाजवाद को जागृत करती रही हैं। आचार्य नरेन्द्र देव का जन्म 31 अक्टूबर 1889 को सीतापुर (उ.प्र.) में हुआ था। इनके पिता बाबू बलदेव प्रकाश पेशे से वकील थे और इन्हें विरासत में अपने पिता से भारतीय संस्कृति व साहित्य मिले। इनके घर जाने माने साहित्यकारों का आना–जाना था। दे शेर कथा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद करने वाले प्रसिद्ध लेखक माधव प्रसाद ने इनका नाम अविनाशी लाल से बदलकर नरेन्द्र देव रखा था। आचार्य नरेन्द्र देव पर स्वामी रामतीर्थ के प्रवचनों का खासा असर पड़ा था, जिससे उन्होंने बचपन में ही रामायण, महाभारत, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, चन्द्रकान्ता, सूरसागर व गीता का गहराई से अध्ययन किया। आचार्य नरेन्द्र देव भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में अपने पिता के साथ प्रथम बार 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मैट्रिक पास करने के पश्चात् जब वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पढने गये तो इनका परिचय महामना मदनमोहन मालवीय से हुआ, लेकिन बाद में जैसे ही कांग्रेस का विभाजन हुआ तो नरेन्द्र देव तिलक और विपिन चन्द्र पाल की ओर आकृष्ट होकर उनके सानिध्य में कार्य करने लगे। जब लोकमान्य तिलक ने कलकत्ता में एक नयी पार्टी की स्थापना की तो आचार्य नरेन्द्र देव के हिन्दी भाषण से वे बहुत प्रभावित हुए। कलकत्ता अधिवेशन के बाद जब नरेन्द्र देव इलाहाबाद लौटे तो इनका भव्य स्वागत किया गया। सन् 1913 में एम.ए. और 1915 में एल.एल.बी. करने के बाद वे भी वकालत करने लगे। कांग्रेस ने जब परिषदों का बहिष्कार किया तो तिलक के अनुयायी होने के नाते इन्होंने इस बहिष्कार को सफल बनाने के लिए जी–जान से कार्य किया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर, वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय कार्यों में जुट गये। पंडित नेहरू ने उन्हें फैजाबाद छोड़कर बनारस में काशी विद्यापीठ का कार्यभार सौंपा। 1926 में डॉ. भगवानदास के त्याग पत्र देने के बाद इन्हें विद्यापीठ का अध्यक्ष बनाया गया। भगवानदास के पुत्र ने इनके नाम के आगे आचार्य शब्द जोड़ दिया। आचार्य नरेन्द्र देव ने, बौद्धधर्म को बखूबी पढ़कर मार्क्सवाद के गहन अध्ययन के पश्चात् एक ऐसा मानस तैयार किया कि वे भारत के जाने–माने नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो गये। उनके पुराने व नवीन विचारों के संगम के कारण वे कांग्रेस में समाजवादी विचारों वाले धड़े के निर्विवाद नेता मान लिये गये। पटना में मई 1934 को वे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने लिये गये। यहीं से भारत में समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ और यह विचारधारा इतनी तीव्रगति से पूरे देश में फैली कि आम जन–जीवन इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। आचार्य नरेन्द्र देव ने अपनी समाजवादी विचारधारा में शनिरन्तर बढ़ते जाना ही संस्कृति का मूलाधार हैश को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मत था कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के साथ–साथ संस्कृति भी बदलती है। हमारा जीवन स्थिर और जड़ नहीं है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और यहीं से सांस्कृतिक जीवन मूल्य भी बदलते हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव ने मजहब से ऊपर राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया। उन्होंने परिवर्तन का अर्थ कदापि यह नहीं माना कि, अतीत के अंश जो उत्कृष्ट और जीवनप्रद है, उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन नये मूल्यों का नरेन्द्र देव ने सदैव स्वागत किया तथा अनावश्यक आचार व्यवहार जो कि समाज व राष्ट्र के लिए हानिकारक है, उनका परित्याग करने पर भी जोर दिया। समाजवादी विचारधारा में परिवर्तन अवश्यंभावी है और हमें नये जीवन के लिए उद्देश्य स्थिर करने होंगे। हमारी संस्कृति सर्वोच्च है और इसमें वे सभी तथ्य व तत्व मौजूद हैं, जिससे नवयुग और नवसमाज का निर्माण हो सकेगा। समाजवादी नेताओं में आचार्य नरेन्द्र देव के प्रति अगाध श्रद्धा थी।

इसका संजीदा उदाहरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस पत्र से झलकता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा मन रो रहा है, कि, आपको क्या लिखूं? अगर हमें यह पता होता कि आप किसान मजदूर पार्टी और समाजवादी दल के विलय की बात से नाराज हैं तो हम ऐसा हरगिज नहीं करते। इस विलय से आचार्य नरेन्द्रदेव को इसलिये धक्का लगा कि विलय से समाजवादी पार्टी का मार्क्सवादी चरित्र नष्ट हो जायेगा। 1948 में जब आचार्य नरेन्द्र देव और डॉ. लोहिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, तब भी वे इस मत के थे कि, हमें कांग्रेस को नहीं छोडना था, परन्तु यह पार्टी के बहुमत का फैसला था, जिसे इन्होंने ध्यान रखकर पुनरू कांग्रेस की ओर मुड़कर नहीं देखा। हालांकि पार्टी में कई संकट आये और विभाजन भी होता रहा। ट्रावनकोर कोचीन में जब प्रथम समाजवादी पार्टी की सरकार ने पुलिस द्वारा प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलवाई जिसमें चार आदमी मारे गये, तब डॉ. लोहिया ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री से त्याग–पत्र मांग लिया था। तब पार्टी महामंत्री होने के कारण इनका कड़ा विरोध हुआ और अंततरू पार्टी के नागपुर सम्मेलन में डॉ. लोहिया से इस्तीफा मांगा गया, समाजवादी विचारधारा वाले दल के इस कार्य का मलाल आचार्य नरेन्द्र देव को अन्त तक रहा। समाजवादी पार्टी इससे दो गुटों में विभाजित हो गयी। लेकिन आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी में इसका विलय हो गया। जनता सरकार टूटने के बाद समाजवादी अलग–अलग पार्टियों में बिखर गये और अब तो यह आन्दोलन प्रायरू खत्म सा ही लगता है। आज नेता राष्ट्र में समाजवाद की बातें अवश्य करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जिन नेताओं ने समाजवाद के जरिये देश की दशा व दिशा बदलने का प्रयास किया, वे अब रह नहीं गये, बल्कि उनके बाद जिनके हाथों में इस आन्दोलन की डोर आयी वे सत्ता से समझौता कर बैठे।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

राजभाषा पखवाड़ा २०२६ के तहत एमसीएल में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन

संबलपुर २५/०९ (संवाददाता): महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा अपने मुख्यालय एवं सभी परिचालन क्षेत्रों में 14 से 28 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा 2026 मनाया जा रहा है। इस दौरान हिंदी के सरकारी कार्यों में प्रयोग को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की हिंदी भाषा एवं साहित्यिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की पहलों के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा हिंदी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राजभाषा पखवाड़े के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, काव्य पाठ, अनुवाद, प्रारूपण, हिंदी टंकण आदि विभिन्न हिंदी भाषा, साहित्य एवं राजभाषा संबंधी गतिविधियों/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को हिंदी में अपनी दक्षता विकसित करने के साथ-साथ राजकीय कार्यों में हिंदी के व्यापक एवं प्रभावी प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए भी विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्हें हिंदी में अपनी रचनात्मकता एवं अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए साहित्यिक एवं रचनात्मक मंच प्रदान किया जा रहा है इन कार्यक्रमों के माध्यम से एमसीएल युवा प्रतिभागियों में हिंदी के प्रति रुचि विकसित करने तथा इसके साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पखवाड़े के समापन अवसर पर 28 सितंबर 2026 को कंपनी मुख्यालय, संबलपुर में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि डॉ. विष्णु सक्सेना, श्री दिनेश दिग्गज, श्री मोहन दुबे एवं डॉ. मोनिका शर्मा अपनी कविताओं, हास्य एवं व्यंग्य से श्रोताओं का मनोरंजन करेंगे। एमसीएल के सभी परिचालन क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी हो रही है। इससे राजभाषा पखवाड़े का दायरा पूरे संगठन में व्यापक हुआ है। राजभाषा पखवाड़े के आयोजन के माध्यम से एमसीएल सभी कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रहा है। साथ ही, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को रचनात्मक, साहित्यिक एवं सहभागितापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से हिंदी से जुड़ने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती समारोह में शामिल हुए मोहन माझी

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार को भुवनेश्वर के जयदेव भवन में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और देश के सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। वह भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं और विचारकों में शामिल थे। उनकी जयंती 25 सितंबर को मनाई जाती है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' और 'अंत्योदय' के विचारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण का लाभ पहुंचाने की सोच आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण की उनकी अवधारणा को याद किया। जयंती समारोह के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर चर्चा की गई। उनके 'अंत्योदय' के विचार में समाज के सबसे कमजोर और वंचित व्यक्ति के उत्थान को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी के साथ विभिन्न गणमान्य लोगों ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। 25 सितंबर को देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी 110वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को याद करते हुए समाज के सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने उनके राष्ट्रसेवा, अंत्योदय और एकात्म मानववाद से जुड़े विचारों को प्रेरणादायी बताया।

तेज हवाओं के बीच हाईवे -516 पर गिरा विशाल बरगद

गंजाम २५/०९ (संवाददाता): ओडिशा के गंजाम जिले में लगातार बारिश और तेज हवाओं का असर जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। छत्रपुर और गोपालपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे-516 पर एक विशाल बरगद का पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। सड़क के बड़े हिस्से पर पेड़ फैल जाने के कारण छत्रपुर, आर्यापल्ली, गोपालपुर और आसपास के क्षेत्रों के बीच यातायात प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर और इमरजेंसी सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर हटाने का काम शुरू किया ।जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में लगातार बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थीं। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ा विशाल बरगद का पेड़ अचानक उखड़कर नेशनल हाईवे-516 पर गिर गया। पेड़ का आकार काफी बड़ा होने के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा बंद हो गया और दोनों तरफ से आने-जाने वाले वाहनों को रुकना पड़ा। राहत की बात यह रही कि पेड़ गिरने के दौरान कोई व्यक्ति या वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। आसपास मौजूद लोग और घर भी बाल-बाल बच गए। यदि पेड़ किसी वाहन या मकान पर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद आसपास के लोगों ने संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। छत्रपुर-गोपालपुर मार्ग व्यस्त सड़कों में शामिल है। इस रास्ते का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन भी करते हैं। ऐसे में सड़क पर विशाल पेड़ गिरने से कुछ ही समय में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। छत्रपुर, आर्यापल्ली और गोपालपुर के बीच आने-जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पूरी तरह साफ नहीं होने तक इस मार्ग पर सामान्य यातायात बहाल करना मुश्किल हो गया। वाहन चालकों को सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा या उपलब्ध वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर और इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। विशाल पेड़ को एक साथ हटाना संभव नहीं होने के कारण उसे अलग-अलग हिस्सों में काटकर सड़क से हटाने का काम शुरू किया गया। अधिकारियों के मुताबिक पूरी सफाई प्रक्रिया में करीब दो घंटे लग सकते हैं। पेड़ की बड़ी शाखाओं और तने को काटने के बाद उन्हें सड़क से हटाना भी चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए कर्मचारियों को सावधानी से काम करना पड़ रहा है, ताकि सफाई अभियान के दौरान किसी तरह की दूसरी दुर्घटना न हो। सड़क साफ होने के बाद ही यातायात को पूरी तरह सामान्य किया जा सकेगा।

इलाके में तेज हवाओं का दौर जारी रहने के कारण राहत और सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों को भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। आसपास अन्य पेड़ों के गिरने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में केवल गिरे हुए बरगद को हटाना ही नहीं, बल्कि आसपास मौजूद कमजोर पेड़ों पर नजर रखना भी जरूरी हो गया है। गंजाम जिले में कई अन्य स्थानों से भी तेज हवा और बारिश के कारण पेड़ उखड़ने या उनकी शाखाएं टूटकर सड़कों पर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। लगातार बारिश से जमीन नरम हो जाती है और तेज हवाओं के दौरान बड़े पेड़ों की जड़ें पकड़ खो सकती हैं। इससे उनके गिरने की आशंका बढ़ जाती है। विशेष रूप से पुराने और बड़े पेड़ों के आसपास खतरा अधिक रहता है। भारी बारिश के कारण मिट्टी में लगातार नमी रहने और फिर तेज हवा चलने से ऐसे पेड़ अचानक गिर सकते हैं। यही कारण है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे वाहन खड़ा करने या लंबे समय तक वहां रुकने से बचना जरूरी होता है। ह॥-516 पर हुई इस घटना ने सड़क यातायात के साथ स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। सड़क के आसपास रिहायशी क्षेत्र होने के कारण पेड़ गिरने की ऐसी घटनाएं घरों और अन्य संरचनाओं के लिए भी खतरा बन सकती हैं। इस घटना में किसी घर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन विशाल पेड़ के गिरने से संभावित खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार बारिश से सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। वाहन चालकों को कम दृश्यता, पानी और तेज हवा के बीच यात्रा करनी पड़ रही है। ऐसे मौसम में अचानक पेड़ या बड़ी शाखा सड़क पर गिरने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में वाहन चालकों को धीमी गति और अतिरिक्त सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। तेज हवा के दौरान बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। पेड़ या शाखाएं बिजली की लाइनों पर गिरने से तार टूटने और खंभों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। ऐसे मामलों में बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ खुले तारों से दुर्घटना का जोखिम भी पैदा हो सकता है। प्रशासन के सामने फिलहाल प्रभावित मार्गों को जल्द से जल्द साफ करने की चुनौती है। सड़क संपर्क लंबे समय तक बाधित होने पर स्थानीय लोगों के साथ एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं और मालवाहक वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है।

महिला से सोने का कंगन चुराने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार

राउरकेला २५/०९ (संवाददाता): राउरकेला पुलिस ने गुरुवार को छेंड कॉलोनी में एक पेट्रोल पंप के पास साधु के रूप में एक महिला से सोने की चूड़ी चुराने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया। आरोपी दिल्ली के करमबीर नाथ (30) और गोरख नाथ (45) और हरियाणा के सोनीपत के राजन नाथ (25) हैं। पुलिस ने कहा कि उनकी पहचान की पुष्टि की जा रही है।

नए स्थान तलाशें जोन ढ्ढ के डीएसपी एमआर प्रधान ने कहा कि साधु के वेश में बदमाशों ने बुधवार सुबह करीब 11.15 बजे छेंड पेट्रोल पंप के पास एक सुनसान जगह पर महिला को रोका और पैसे की मांग की। जब उसने इनकार कर दिया, तो उन्होंने कथित तौर पर उसे हिरासत में ले लिया और उससे कहा कि उसे शाप दिया जाएगा। प्रधान ने कहा, इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर महिला से सोने की चूड़ी छीन ली।

पीड़िता ने शोर मचाया जिसके बाद राहगीर मौके पर पहुंचे और तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन के आईआईसी आरएन पात्रा ने कहा कि पीड़ित महिला की सोने की चूड़ी और आरोपी के कब्जे से 1,450 नकद बरामद किए गए। इससे पहले, तीनों ने कथित तौर पर इसी चाल का उपयोग करके बसंती कॉलोनी में एक युवक से लगभग क्ष्,700 लूट लिए थे। वे कथित तौर पर धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पने के लिए नवंबर 2025 में बंडामुंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में भी शामिल थे। तीनों पर बीएनएस की धारा 308(5) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया और अदालत में पेश किया गया।

कार्यस्थल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आर.एस.पी. में 'मेरा क्षेत्र, मेरी जिमेदारी' एप्लिकेशन लॉन्च

राउरकेला २५/०९ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के सी. एंड आई.टी. एवं डिजिटलीकरण विभाग द्वारा विकसित इन-हाउस डिजिटल पहल एम.ए.एम.आर. (मेरा क्षेत्र, मेरी जिम्मेदारी) एप्लिकेशन का शुभारंभ 21 सितंबर, 2026 को मंथन सम्मेलन कक्ष में आर.एस.पी. के निदेशक प्रभारी, श्री आलोक वर्मा ने किया। इस अवसर पर आर.एस.पी. के कार्यपालक निदेशक, मुख्य महा प्रबंधक, विभागाध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 'हमारी सुरक्षा, हमारी जिम्मेदारी' के सिद्धांत पर आधारित यह एप्लिकेशन कर्मचारियों को अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में सुरक्षा की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है। फोटो आधारित रिपोर्टिंग के माध्यम से कर्मचारी असुरक्षित कार्यों, असुरक्षित परिस्थितियों, घटनाओं एवं असामान्य कार्य-पद्धतियों की त्वरित पहचान कर उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दर्ज किए गए अवलोकनों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड, ट्रैक एवं व्यवस्थित तथा समयबद्ध तरीके से संबोधित किया जा सकता है। एम.ए.एम.आर. एप्लिकेशन में विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों के लिए अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं। एम.ए.एम.आर. कैप्टन एवं सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित मामलों को दर्ज कर सकते हैं, उनकी स्थिति अपडेट कर सकते हैं तथा सुरक्षा संबंधी अवलोकनों की निगरानी कर सकते हैं। वहीं, विभागाध्यक्ष (एच.ओ.डी.), सुरक्षा प्रमुख (एच.ओ.एस.) एवं विभागीय सुरक्षा अधिकारी (डी.एस.ओ.) अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों को देख सकते हैं, प्रगति की निगरानी कर सकते हैं तथा टिप्पणियों एवं अवलोकनों के आधार पर लंबित कार्रवाइयों में तेजी ला सकते हैं। उच्च प्रबंधन के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पूरे संयंत्र में दर्ज किए गए सुरक्षा मामलों का समग्र विवरण, उनकी स्थिति, की गई कार्रवाई एवं अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी मिलती है।

ये सुविधाएं सुरक्षा प्रबंधन में बेहतर दृश्यता, समयबद्ध हस्तक्षेप तथा डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायक होंगी। इस अवसर पर मुख्य महा प्रबंधक (एन.पी.एम. एवं डिजिटलीकरण), श्री आर.के.मुदुली ने एप्लिकेशन के विकास की यात्रा एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। मुख्य महा प्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं), श्री हीरालाल महापात्र ने संयंत्र की सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने में एप्लिकेशन के प्रभावी उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। महा प्रबंधक (सी. एंड आई.टी.), श्रीमती सुमिता भट्टाचार्य ने डैशबोर्ड का प्रदर्शन किया तथा सुरक्षा निगरानी एवं दृश्यता में इसकी भूमिका को समझाया। एम.ए.एम.आर. एप्लिकेशन गूगल प्ले-स्टोर पर उपलब्ध है और आर.एस.पी. के अधिकृत कर्मचारी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह पहल सक्रिय एवं पूर्व-सावधानी आधारित सुरक्षा प्रबंधन, मानकीकृत हाउसकीपिंग तथा अनसुलझे खतरों के प्रति शून्य-सहिष्णुता की कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे अधिक सुरक्षित एवं डिजिटल रूप से सक्षम कार्यस्थल के निर्माण में सहायता मिलेगी।

हल्दी की उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए एमसीएल ने किया समझौता ज्ञापन

संबलपुर २५/०९ (संवाददाता): महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने कंधमाल जिले में हल्दी की उन्नत खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से कंधमाल जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। लगभग 1 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इस सीएसआर पहल के तहत किसानों को उन्नत सलेम किस्म के हल्दी राइजोम का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती की पद्धतियों पर प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य फसल उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की कृषि आय में सुधार करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जिससे क्षेत्र में हल्दी आधारित आजीविका को मजबूती मिलेगी। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के साथ तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराकर यह परियोजना किसानों को उन्नत खेती के तरीकों को अपनाने तथा हल्दी की खेती के समग्र मूल्य को बढ़ाने में सहायता करेगी। यह पहल ओडिशा के आकांक्षी जिले कंधमाल में टिकाऊ आजीविका विकास और कृषक समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एमसीएल ने अब तक कंधमाल जिले में 21.57 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो जिले में समावेशी और टिकाऊ विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।